किसान कर्ज़ का मामला

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

16 मार्च, 2022

6 साल में 53% बढ़ा किसानों का कर्ज, केन्द्र ने RS. को बताया

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले छह वर्षों में किसानों के कर्ज में 53 फीसदी की वृद्धि हुई है।

2020-21 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए बकाया कृषि ऋण 2015-16 मे ₹12 लाख करोड़ की तुलना में ₹18.4 लाख करोड़ से अधिक था, ऐसे ऋण रखने वाले किसानों के खातों की संख्या भी 6.9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ से अधिक हो गई है।

भारतीय संघ मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल वहाब के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आरबीआई से प्राप्त डेटा, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने किसानों के ऋण और ऋण माफी का विवरण माँगा था।

जवाब में, राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि केंद्र ने पिछले छह वर्षों में कोई ऋण माफी लागू नहीं की है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसके बजाय, उन्होंने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए की गई विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया, जिसमें ब्याज सबवेंशन योजनाएँ, छोटे किसानों के लिए संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण और आय सहायता और कृषि बीमा योजनाएँ शामिल हैं। यह देखते हुए कि किसानों को संस्थागत ऋण की तह में लाने के प्रयास किए गए थे।, परिणामस्वरूप अनौपचारिक ऋणों की कृपा पर छोड़ दिया गया।

महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज का बोझ सबसे अधिक है, छह साल की अवधि में बकाया राशि में 116% की वृद्धि हुई है।

निरपेक्ष रूप से भी, महाराष्ट्र के किसानों पर कृषि ऋण के रूप में सबसे अधिक 5.5 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। संयोग से, राज्य में लगातार किसान आत्महत्याओं की संख्या सबसे अधिक है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया है।

जिन अन्य राज्यों में किसानों के कर्ज के बोझ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, उनमें ओडिशा (76%), तमिलनाडु (68%), आंध्र प्रदेश (65%) और गुजरात (64%) शामिल हैं। केवल कुछ राज्यों ने इस प्रवृत्ति को कम किया, कर्नाटक में 37% और पंजाब में 4.5% की मामूली गिरावट दर्ज की गई।

श्री वहाब ने कहा, "डेटा स्पष्ट रूप से उन किसानों की दुखद दुर्दशा को उजागर करता है जो कर्ज की आसमान छूती वृद्धि के भार से कुचले जा रहे हैं।" उन्होंने कहा, "[प्रधानमंत्री] 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहे हैं और इसके बजाय 2022 तक उनके कर्ज को दोगुना कर दिया है।"

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. कृषि ऋण माफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. कृषि ऋण माफी से बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है।
2. इससे सरकार का राजकोषीय घाटा और ब्याज का बोझ बढ़ता है

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1
(ख) केवल 2
(ग) 1 और 2 दोनों
(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements regarding Farm loan waiver.

1. Farm loan waivers tend to increase the NPAs of the banks.
2. It increases the fiscal deficit and interest burden of the government.

which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only
(b) 2 only
(c) Both 1 and 2
(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कृषि ऋण माफी क्या है? किसानों के कर्ज से संबंधित विभिन्न मुद्दों और उसके समाधानों पर चर्चा करें।

(250 शब्द)

Q. What is farm loan waiver? Discuss the various issues related with Farmers debts and its solutions.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।